शीतयुद्ध के बाद के काल में चीनी वैदेशिक नीति

Paper- VI

Dr. Khalid

1990 वाले दशक में शीतयुद्ध के अंत के समय से लेकर अब तक चीनी विदेश नीति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व (Elements of Continuity and Change) देखने को मिलते हैं। निरंतरता के तत्व इस तथ्य के परिणाम हैं कि शीतयुद्ध के बाद के काल में भी वैदेशिक नीति के लक्ष्य भी बुनियादी रूप से वही रहे हैं जो Mao के जमाने से हैं, ये लक्ष्य हैं:

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राप्ति ~~तथा चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण एवं महान राष्ट्र के दर्जे की प्राप्ति।~~

(ii) ~~चीन के लिए~~ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के लिए एक महत्वपूर्ण एवं महान राष्ट्र के दर्जे की प्राप्ति

(iii) तीसरी दुनिया ~~के लिए~~ में साम्यवादी विचारधारा के प्रोत्साहन तथा अपने प्रभाव की प्राप्ति

परन्तु साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों तथा उन परिस्थितियों में चीन की स्थिति के सम्बंध में समझदारी में परिवर्तन के चलते वैदेशिक नीति में हेर-फेर एवं समायोजन होते रहते हैं। 1980 वाले दशक के प्रारम्भ में चीन की आंतरिक राजनीति में Four Modernizations की जो नीति शुरू की गई उसका शीतयुद्ध के बाद के काल में भी अवलम्बन होता रहा है। उस नीति के अनुरूप ही चीनी विदेश नीति में हेर-फेर अथवा परिवर्तन एवं समायोजन की नीति अपनाई गई है।

1990 वाले दशक के प्रारम्भ में शीतयुद्ध के अंत, सोवियत संघ सहित अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से साम्यवादी व्यवस्था का अंत, सोवियत संघ का एक राष्ट्र के रूप में अंत तथा पूर्व सोवियत संघ के सबसे बड़े उत्तराधिकारी रूस तथा पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते सहयोग आदि जैसे तथ्यों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन ला दिया। विश्व के अधिकांश देशों की भांति चीन के नीति निर्धारकों के सामने भी उन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास के क्रम में नीति निर्धारकों ने फिर से परिवर्तन एवं समायोजन की नीति को अपना लिया।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए शीतयुद्ध के बाद की चीनी विदेश नीति की प्रमुख प्रवृत्तियों (तत्वों, विशेषताओं) को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है:

1990 वाले दशक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों में बुनियादी परिवर्तनों से यद्यपि चीन चिंतित

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

Scanned with CamScanner

पाने में अपनी अक्षमता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिकता का परिचय दिया। चीन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए USA तथा अन्य पश्चिमी देशों के सहयोग की आवश्यकता थी। उधर सोवियत संघ से साम्यवादी व्यवस्था का अंत, एक राष्ट्र के रूप में उसके विघटन तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्व सोवियत संघ के सबसे बड़ा उत्तराधिकारी रूस द्वारा पश्चिमी देशों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण के चलते चीन की वह लाभदायक स्थिति भी नहीं रह गई जो शीतयुद्ध के काल में थी। ऐसी स्थिति में USA तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने मतभेदों को उजागर करने के बजाय उसने मोटे तौर पर पश्चिमी देशों के साथ सहयोग की नीति के अवलम्बन की घोषणा की।

—शीतयुद्ध के अंत के बाद चीन ने रूस से पश्चिमी देशों के साथ सहयोग की नीति की घोषणा की और कई मामलों में उनके साथ सहयोग भी किया। किन्तु यह सहयोग अधिक आगे नहीं बढ़ सका। चीन ने यह महसूस किया कि सोवियत संघ के अंत के बाद उसके प्रति USA का रुख कड़ा होने लगा है।

USA के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने चीन में मानव अधिकारों का मुद्दा बार-बार उठाया है। ऐसी स्थिति में चीनी नेतृत्व की यह सोच है कि पश्चिमी देश चीन की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के महत्वपूर्ण स्थान का अंत देखना चाहते हैं। चीन में कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह विचार व्यक्त किया है कि शीतयुद्ध के बाद के काल में USA एक घमण्डी राष्ट्र (Arrogant Nation) जैसा व्यवहार कर रहा है और पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। पिछले 20 वर्षों में चीनी विदेश नीति इस बात से संबंधित रही है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में USA के प्रभाव को रोका जाए। Russia एवं [illegible] के साथ मिलकर USA के प्रभाव को रोकने के लिए सहमति को बढ़ावा देने के सम्बंध में चीनी प्रयासों को इसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। रूस के साथ अच्छे सम्बंध बनाए रखने के लिए समय समय

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श इस प्रयास का प्रतिफल है।

शीतयुद्ध के अंत के पूर्व सोवियत संघ तथा USA के बीच तनाव शैथिल्य की जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी उसके प्रति 1980 वाले दशक के प्रारम्भ में चीन ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। यह उल्लेखनीय है कि 1970 वाले दशक में चीन ने USA-USSR Detente की प्रक्रिया के प्रति आशंका व्यक्त की थी। परन्तु 1980 वाले दशक के प्रारम्भ से चीन ने यह विचार व्यक्त करना शुरू किया कि Detente से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। चीन ने दोनों देशों से आणविक हथियारों की होड़ पर रोक लगाने की भी अपील की। Detente तथा निःशस्त्रीकरण के प्रति यह नवीन दृष्टिकोण अवश्य ही युद्ध के सिद्धांत सम्बंधी Mao के सिद्धांत से भिन्न था।

अमेरिका तथा सोवियत संघ के तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया

1980 वाले दशक में Theory of Three Worlds (तीन दुनिया के सिद्धांत) पर बल देते हुए चीन ने तृतीय विश्व अर्थात् विकासशील देशों के साथ संबंध सुधार का भरपूर प्रयास किया है। तृतीय विश्व के देशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी पुरानी नीति का उसने परित्याग कर दिया है। यद्यपि तीसरी दुनिया के सिद्धांत का प्रतिपादन Mao ने ही किया था। परन्तु इसके आधार पर विकासशील देशों में चीन की छवि सुधारने तथा उनके साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास Mao के बाद के राजनीतिक नेतृत्व ने किया। शीतयुद्ध के बाद Theory of Three Worlds बहुत प्रासंगिक नहीं रह गया है तथापि विकासशील देशों के साथ संबंध सुधारने तथा उनके हितों के हिमायती के रूप में अपने को पेश करने का प्रयास Post-Cold War Period में भी जारी रखा है। भारत तथा अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर WTO तथा अन्य आर्थिक संगठनों में विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाना चीनी नीति निर्धारकों का प्रयास रहा है।

दुनिया के सिद्धांत

युद्ध के बाद के

1990 वाले दशक में चीनी वैदेशिक नीति में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृति उभरकर सामने आयी है। अपने पड़ोसी देश के साथ संबंधों के सुधार में उसने अभिरुचि दिखाई है। वियतनाम, दक्षिण कोरिया, भारत तथा जापान ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ चीन ने अपने सम्बंधों में सुधार में दिलचस्पी दिखाई है। भारत के साथ

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

Scanned with CamScanner

अपने सम्बंध सुधारने के लिए निश्चित रूप से चीन ने अपने वैदेशिक नीति में लचीलापन एवं व्यवहारिकता का प्रदर्शन किया है। चीन ने अपने द्वारा जारी संशोधित मानचित्र में सिक्किम पर भारत की सम्प्रभुता को स्वीकार कर संबंध सुधारने के दिशा में दिलचस्पी ~~ली है~~ दिखाई है।

वास्तव में, चीन USA के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है और वह इस क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाये रखना चाहता है जिससे USA की सैनिक उपस्थिति में वृद्धि नहीं हो और आवश्यकता पड़ने पर भारत का सहयोग प्राप्त हो सके।

शीत युद्ध के बाद की चीनी विदेश नीति की अबतक की चर्चा से यह बात सामने आती है कि चीन के विदेश नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। चीनी वैदेशिक नीति के निर्धारकों एवं उन्मुखीकरण में विचारधारा की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है जितनी 1950 वाले तथा 1960 वाले दशकों में थी। आज निश्चित रूप से चीनी विदेश नीति दिनोंदिन व्यवहारिकता से अधिक प्रेरित होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों के चलते चीन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी विदेश नीति में विचारधारा के स्थान पर व्यवहारिकता को अधिक स्थान दे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि

"The ~~Chise~~ Chinese foreign policy in the post-Cold period has been inspired by ~~prap~~ pragmatism and ideology has been relegated to the background."

~~The Chinese foreign policy in the post-cold war period has been inspired by pragmatism and ideology has been been relegated to the background.~~

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

Scanned with CamScanner